पाकिस्तान की परमाणु नीति ब्लेकमेल की नीति है

डॉ0 शमीम राइन*

पाकिस्तान की परमाणु नीति की स्पष्ट व्याख्या जुल्फिकार अली भुट्टो के सत्ता संभालने के बाद दिखायी देती है। पाकिस्तान में सत्ता सम्भालने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि 'हम भारत के साथ हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहेंगे, जब तक कि निर्णायक युद्ध नहीं हो जाता' परन्तु 1971 में पाकिस्तान के बुरी तरह पराजित हो जाने पर उन्होंने कहा कि 'किसी भी समस्या का हल शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा ही किया जा सकता है'' जिसका प्रमाण उन्होंने 1971 के हार के बाद भारत के साथ शिमला समझौता करके दिया। परन्तु आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि ''हम घास की रोटी खा लेंगे परन्तु परमाणु बम अवश्य बनायेंगे।'' भुट्टो ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि ''आज संसार की दूसरी सभ्यताएं हिन्दू, यहूदी, इसाई सबके पास आणविक हथियार का निर्माण हो चुका है। सिर्फ इस्लाम ही इस आणविक हथियार से वंचित है।''[1] स्व0 भुट्टो को परमाणु बम बनाने की चेतना इतना अधिक जागृत हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री बनने के दो महीने बाद ही अपने वैज्ञानिकों और अधिकारियों की, 1972 में मुल्तान में एक बैठक आयोजित की, जिसमें इस प्रोजेक्ट का नामकरण '706' रखा गया, इस प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ हो गया, 1973 में कनाडा से बना बनाये एटमी रियेक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम ईधन के तौर पर उपयोग में लाया गया।[2]

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण आणविक हथियार नहीं बना सकता था, अतः भुट्टो ने इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों की 1974 में बैठक आयोजित की, जिसमें कर्नल गद्दाफी ने यह स्वीकार किया कि आणविक बम बनाने में जितना व्यय होगा उसका आधा व्यय हमारे देश द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रकार आर्थिक सहायता के लिए गद्दाफी तैयार हुए।[3] इसके अतिरिक्त कई मुस्लिम देशों ने भी आर्थिक सहायता दी। पाकिस्तान ने इसलिए अपने परमाणु बम को 'इस्लामी बम' नाम दिया। इस तरह से पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्रों का धन और जन दोनों समर्थन हासिल करने में सफल रहा। कर्नल गद्दाफी ने अल्जीरिया से पाकिस्तान को यूरेनियम आक्साइड दिलवाया। जिससे बम के लिए प्लूटोनियम तैयार किया जा सके। पाकिस्तान की सरकार ने डॉ0 कादिर के नेतृत्व में इस्लामाबाद के पास 'काहुटा' में एटमिक केन्द्र कार्य करना प्रारम्भ किया।[4]

भुट्टो का परमाणु बम का सपना साकार भी नहीं हो पाया क्योंकि 5 जुलाई, 1977 को जनरल जिया उल हक ने मार्शल लॉ के माध्यम से राष्ट्रपति पद अपने हाथ में कर लिया, भुट्टो को कैद कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया और अंत में फांसी दे दी गयी। इस बीच भुट्टो द्वारा प्रारम्भ किया गया प्रोजेक्ट '706' प्रभावित हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जनरल हक ने परमाणु बम बनाने में उतने ही उतावले हो गये थे जितना कि स्व0 भुट्टो थे। जनरल हक ने '706 प्रोजेक्ट' का नाम बदलकर 'डॉ0 कादिर

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, सकलडीहा पी0जी0 कालेज, सकलडीहा, चन्दौली

खाँ' प्रोजेक्ट कर दिया। अभी कुछ वर्ष पहले ही इस वैज्ञानिक पर परिशोधन संयन्त्र के पूर्जे चुराने का आरोप लगाया गया था। फिर भी कादिर खाँ को इसमें सफलता मिली और उन्होंने यह बयान दिया कि अब पाकिस्तान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है।[5]

फरवरी, 1984 में डॉ0 कादिर खाँ ने पाकिस्तान में 'दैनिक नवाये वक्त' के एक भेट में बताया कि 'पाकिस्तान ने यूरेनियम को विखण्डित करने में सफलता प्राप्त कर ली है जो कि पश्चिमी देश सोच भी नहीं सकते थे। कादिर खाँ ने भारत के बारे में कहा कि ''भारत को इसमें पहले ही सफलता प्राप्त हो चुकी है, जब कि मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि इस बीच के अंतराल को यथाशीघ्र समाप्त कर दूँ क्योंकि इसमें भारत ने हमें 6 वर्ष पीछे छोड़ दिया है। जब बीच में एक पत्रकार ने पूछा कि आप अपने परमाणु बम का विस्फोट कर चुके हैं या करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि 'यह प्रश्न ऐसा है कि इसके माध्यम से हमारे देश को मिल रही आर्थिक सहायता अवरूद्ध हो सकती है।[6]

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ओमान की यात्रा के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कहा कि ''भारतीय नेता हमारे ऊपर प्रारम्भ से ही परमाणु बम को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह सब निराधार है। जिया ने परमाणु नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है।[7]

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया ने संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बनाये रखने के लिए 'पांच सूत्रीय' प्रस्ताव रखा था। जिसमें मुख्य रूप से भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना था। भारत और पाकिस्तान आपस में यह निश्चय करें कि दोनों देशों के परमाणु केन्द्रों को दोनों देशों के प्रतिनिधि बारी–बारी से निरीक्षण करें साथ ही साथ यह निश्चित करें कि न तो हम परमाणु बम का निर्माण करेंगे और न ही किसी दूसरी देश से परमाणु बम प्राप्त करेंगे।

जनरल जिया के इस पांच सूत्रीय प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अस्वीकार करते हुए कहा था कि ''हम पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से विश्वास करें जबकि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में चल रहा है, इसके बाद कैसे पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है।[8]

पाकिस्तान का प्रथम परमाणु संयंत्र 'कानूप' है जो कि 37 मेगावाट शक्ति का है, करॉंची से 13 किमी0 पश्चिम में स्थित है, जिसका निर्माण कनाडा की सहायता से किया गया। इसके निर्माण हेतु कनाडा की सरकार ने पाक को 24 मिलियन डालर तथा टरबो जेनेरेटर हेतु जापान ने 36 मिलियन की सहायता की थी।[9] परन्तु जब 1976 में पाकिस्तान इसके अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण हेतु तैयार नहीं हुआ तब कनाडा सरकार ने संपूर्ण सहायता बन्द कर दी। इसके अतिरिक्त लाहौर में यूरेनियम शोधक संयंत्र, चश्मा बाध में राइ ईंधन संयन्त्र तथा काहुटा में परिष्कृत यूरेनियम संयंत्र स्थित है। इतना ही नहीं पाकिस्तान, सन् 1992 तक 160 अतिरिक्त परमाणु रियेक्टरों को स्थापित करने की योजना निर्धारित की है।[10] श्री भुट्टो को फांसी देने के बाद सैनिक प्रशासक जनरल जिया ने परमाणु कार्यक्रम काफी तीव्र कर दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप तथा भारत का परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

पाकिस्तान ने हमेशा परमाणु बम बनाने का खण्डन करता चला आ रहा था लेकिन बाद में पाकिस्तान के प्रशासक (जनरल जिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने का अधिकार है) जबकि जुलाई 1985 में नई दिल्ली आये पाक प्रतिनिधि मण्डल से इस संदर्भ में भारत में जो वार्ता हुए उसमें इस बात से इंकार किया गया कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। इस परस्पर विरोधी वक्तव्यों का अर्थ क्या हो सकता है ? वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तान शीघ्रातिशीघ्र बम का निर्माण करना चाहता है। क्योंकि वह अपने संयंत्र पर इजरायली प्रहार के डर (क्योंकि इजराइल ने पाक के परमाणु कार्यक्रम को इराक के परमाणु कार्यक्रम से भी बड़ा खतरा मानता है) तथा इस्लामिक देशों के नेतृत्व के लिए बम निर्माण के कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कर लेना चाहता है।

पाकिस्तान के परमाणु नीति संबंधी वक्तव्य काफी कुटनीति लगते हैं। एक तरफ तो वह परमाणु बम के निर्माण कार्य में लगा है दूसरी तरफ उसका विचार है कि भारत व पाकिस्तान अपने–अपने परमाणु संयंत्रों में संयुक्त निगरानी के लिए खोल दें। पाकिस्तान के उक्त प्रस्ताव के पीछे निम्न तथ्य छुपे प्रतीत होते हैं।[11]

1– यदि पाकिस्तान भारत के परमाणु संयंत्रों को देख लेगा तो भारत के उन्नत तकनीक को चुराये जाने की पूरी संभावना है। जब पश्चिम के गोपनीय संयंत्रों में काम करते हुए पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य चुरा लिये तो भारत की खुल्लम–खुल्ला निगरानी से वे कुछ और भी कर सकते हैं। इससे भी बड़ा भय यह है कि भारत का हर रहस्य पश्चिम देशों के हाथ में आसानी से चला जायेगा। दूसरी ओर यदि भारत ने पाकिस्तानी संयंत्रों को देख भी लिया तो भारत को इस जानकारी से किसी लाभ की संभावना नहीं है।

2– संयुक्त निगरानी प्रस्ताव का दूसरा उद्देश्य दक्षिण एशिया को परमाणु क्षेत्र बनाने से संबंधित है।

सबसे रोचक बात यह है कि पाकिस्तान अपने संयंत्रों की जांच भारत से कराने को तैयार है लेकिन वियना के परमाणु अभिकरण से नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? यही नहीं, यदि पाकिस्तान का कार्यक्रम सचमुच शांतिपूर्ण है तो उसे यह चाहिए कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करें और अपने परमाणु संयंत्रों को अन्तर्राष्ट्रकीय जांच होने दें।[12] पाकिस्तान के इरादे यदि पाक होते तो उसे आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ–साथ भारत की तरह अपना परमाणु बजट प्रकाशित करना चाहिए। ये सभी तथ्य इस बात का संकेत देते हैं कि पाकिस्तानी शीघ्रातिशीघ्र इस्लामिक बम से लैस होकर दक्षिण एशिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ख्याति प्राप्त करने की योजना पर चल रहा है।[13]

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1– कौशिक बी0एम0 एण्ड मेहरोत्रा ओ0एन, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम, नई दिल्ली, 1980, पृष्ठ–7.

2– साप्ताकि हिन्दुस्तान, 4–10 अगस्त, 1985, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ – 66.

3– दिनमान, 13–19 सितम्बर, 1981, पृष्ठ–29.
4– साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 4–10 अगस्त, 1985, पृष्ठ–6.
5– धर्मयुग 7–13 जुलाई, 1985, टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ–24.
6– साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 28 जुलाई, 1985, पृष्ठ–7.
7– हिन्दुस्तान टाइम्स, 12 जुलाई, 1987.
8– नव भारत टाइम्स, 26 अक्टूबर, 1985.
9– पालित डी0के0 एण्ड लम्बूदिरी पी0के0एस0, पाकिस्तानी इस्लामिक बम, पृष्ठ–2.
10– वही.
11– Pakistan Horizon, Vol. 28(3), 1975, p. 145.
12- See Bhawani Sengupta, Nuclear weapons : Policy Options for India (New Delhi, 1982), p. 4.
13- G.C. Raju Thomas, "Security Relationship in Southern Asia : Difference in the Indian & American perspectives Asian Survey, Vol. 2, No. 7, July, 1981, pp. 689-709.

****